

प्रेषक,

अरुणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-8

देहरादून: दिनांक 27 जुलाई, 2015

विषय:- वाणिज्य कर अधिकरण के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण सहायक निबन्धक सेवा नियमावली, 2015 का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मंत्रिमण्डल के आदेश के क्रम में वाणिज्य कर अधिकरण के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण सहायक निबन्धक सेवा नियमावली, 2015 का प्रख्यापन वित्त अनुभाग-8, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-631/2015/26(100)XXVII(8)/07, दिनांक 23.07.2015 द्वारा कर दिया गया है। अतः संदर्भगत सेवा नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या-637/2015/26(100)XXVII(8)/07, तददिनांक।प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध सहित की अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी की मुद्रित 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में उपलब्ध करा दें। (संलग्नक)
- 5- एन0आई0सी, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
- 6- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव।

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण में सहायक निबंधक की सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण सहायक निबंधक सेवा नियमावली, 2015

भाग-1-सामान्य

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण सहायक निबंधक सेवा नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्राप्ति 2. उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण सहायक निबंधक सेवा एक राजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह “ख” का पद सम्मिलित है।

परिभाषाएं 3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ख) “भारत का नागरिक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाता हो;

(ग) “संविधान” से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(घ) “सरकार” से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) “राज्यपाल” से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(च) “सेवा के सदस्य” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस नियमावली के उपबन्धों या इस नियमावली के लागू होने से पहले प्रवृत्त नियमावली तथा आदेशों के उपबन्धों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्त हो;

(छ) “सेवा” से अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड के प्रशासकीय नियंत्रण में सहायक निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण सेवा अभिप्रेत है;

(ज) “मौलिक नियुक्ति” से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो;

(झ) “भर्ती का वर्ष” से किसी कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4.(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसके अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसके अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उपनियम(1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश पारित न कर दिए जायें, उतनी होगी, जो संलग्न "परिशिष्ट" में दी गई है;

परन्तु

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं अथवा राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा के पदों पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित स्रोत से की जायेगी-

(एक) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड-2, वेतनमान, 9300-34800 (ग्रेड वेतन, 4600) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अपने संवर्ग में न्यूनतम 12 वर्ष की निर्वाध सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो) ऐसे वैयक्तिक सहायक, ग्रेड-1, वेतनमान, 9300-34800 (ग्रेड वेतन, 4200) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अपने संवर्ग में कम से कम 5 वर्ष की निर्वाध सेवा पूर्ण कर ली हो,

परन्तु यह है कि इन पोषक पदों पर निर्धारित सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त अधिक सेवाकाल वाले कार्मिक को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रदत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 7. नियुक्ति प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

की प्रक्रिया

8. (1) सेवा संवर्ग के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती 'अनुपयुक्त' को अस्वीकार करते हुए, 'ज्येष्ठता' के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से ऐसे कर्मचारियों में से चयन करके की जायेगी जो भाग 3 के नियम 5 के अन्तर्गत पदोन्नति के पात्र हैं।
- (2) चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-


(एक) अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण	अध्यक्ष / नियुक्ति प्राधिकारी
(दो) सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण	सदस्य
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ग के पदों में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा जिनके लिए चयन किया जाना है।
- (4) पात्रता के क्षेत्र के अन्दर आने वाले समस्त अभ्यर्थियों की पात्रता-सूची उनकी चरित्र पंक्तियों एवं ऐसे अन्य सभी अभिलेख सहित, यदि कोई हो, जो आवश्यक हो और इस प्रयोजन के लिए तर्क संगत हो, चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।
- (5) जिस पद के लिये चयन करना है, उसके लिये पदोन्नति के पात्र अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिये चयन समिति उन सभी के मामलों में उनकी चरित्र पंक्तियों और अन्य अभिलेखों के सन्दर्भ में, जो उनके समक्ष रखे गये हैं, विचार करेगी।
- (6) चयन समिति द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों के नामों को उस संवर्ग में, जिसमें पदोन्नति की गयी है, उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखा जायेगा। इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची में अभ्यर्थियों के नाम उन रिक्तियों की संख्या के दुगुने होंगे, जिनके लिये चयन किया जाना हो।
- (7) एतदपश्चात्, चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी के पदोन्नति सम्बन्धी आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्गत किये जायेंगे।

भाग पाँच-ज्येष्ठता, परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

ज्येष्ठता 9. (1) एतदपश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता) नियमावली, 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिससे उनके नाम उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किए जाते हैं;

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्ति किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा;

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाते हैं, तो अभ्यर्थियों की परस्पर

✓ 

ज्येष्ठता वही होगी जो उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता) नियमावली, 2002 के नियम 15 के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

- (2) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है;

परन्तु उपलब्ध यह है कि:-

- (एक) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची में) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रख जायेगा।
- (दो) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ, संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में, किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध की गयी है।

परिवीक्षा 10.(1) सेवा में मौलिक रिक्तियों में या उनके प्रति नियुक्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

- (2) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित पद या किसी अन्य समान या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की गणना करने के प्रयोजन हेतु अनुज्ञा दे सकता है।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, वैयक्तिक मामलों में परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है जिसमें वह उस निश्चित तिथि को विनिर्दिष्ट करेगा जब तक अवधि बढ़ायी गई हो;

परन्तु उपबन्ध यह है कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

- (4) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की अवधि के अन्त में या बढ़ायी गई परिवीक्षा की अवधि में, जैसी भी स्थिति हो, यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह अन्यथा समाधान करने में असफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार (लिएन) नहीं है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
- (5) कोई व्यक्ति, जिसकी सेवायें उप-नियम (4) के अन्तर्गत प्रत्यावर्तित की जाय या समाप्त कर दी जाय, किसी प्रतिकर को पाने का हकदार नहीं होगा।

करण 11. (1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा की अवधि के अन्त में अपने पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—
 (क) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया गया है,
 (ख) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित है, और
 (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

(2) जहां उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्ध के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए पारित आदेश, कि सम्बन्धित कार्मिकों ने परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

भाग छः—वेतन इत्यादि

नियमान 12. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होगा:—

क्र० सं०	पद का नाम	वेतन बैंड/ वेतनमान नाम	वेतन बैंड/ वेतनमान	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1.	सहायक निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड	वेतन बैंड-2	रू०-9300-34800	रू० 4600

परिवीक्षा अवधि में वेतन 13. (1) परिवीक्षा अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी।

भाग सात—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 14. किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी संस्तुति, चाहे लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

15. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

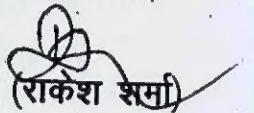
शर्तों का

नियम 16. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन, उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल कर देगी जो वह उस मामले के सम्बन्ध में न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे।

व्यावृत्ति

17. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,


(राकेश शर्मा)

अपर मुख्य सचिव।

in pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 63/2015/26(100)/XXVII(8)/07, Dated 23 July, 2015 for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
FINANCE SECTION-8
NO-63/2015/26(100)/XXVII(8)/07
DEHRADUN:: DATED 23 JULY, 2015

Notification
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 'Constitution of India' and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Commercial Tax Tribunal Assistant Registrar Service :-

The Uttarakhand Commercial Tax Tribunal Assistant Registrar Service
Rules, 2015

Part-I-General

**Short title and
commencement**

1. (1) These rules may be called "The Uttarakhand Commercial Tax Tribunal Assistant Registrar Service Rules 2015."
- (2) They shall come into force at once.

Status of the service

2. The Uttarakhand Commercial Tax Tribunal Assistant Registrar Service is a Gazetted service, comprising Group 'B' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-


- (a) "Appointing Authority" means the Chairman, Commercial Tax Tribunal, Uttarakhand;
- (b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
- (c) "Constitution" means the Constitution of India;
- (d) "Government" means the State Government of Uttarakhand;
- (e) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;
- (f) "Member of the service" means a person substantively appointed under the provisions of these rules or rules and orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;
- (g) "Service" means Commercial Tax Tribunal Assistant Registrar service under the administrative control of the Chairman, Commercial Tax Tribunal, Uttarakhand;

**परिशिष्ट
{देखिये नियम 4(2)}**

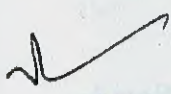
सेवा में और उसमें सम्मिलित विभिन्न श्रेणी के पदों की वर्तमान संख्या—

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या		कुल योग
		स्थायी	अस्थायी	
1.	सहायक निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण	—	1	1

आज्ञा से,


(संकीर्ण शर्मा)

अपर मुख्य सचिव।



(i) "Substantive Appointment" means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the Service made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions, issued by the Government; and.

(i) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part- II- Cadre

Cadre of Service 4. (1) The strength of the Service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1) be as given in the annexed 'Appendix';

Provided that: --

- (i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation.
- (ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Part- III- Recruitment

Source of Recruitment 5. Recruitment to the posts in the service shall be made by promotion through a Selection Committee on the basis of Seniority, subject to rejection of unfit from the following sources-

- (i) From amongst such substantively appointed Administrative Officer Grade-II, in the pay scale of Rs 9300-34800 (Grade Pay, 4600) who have completed 12 years continuous service in his cadre on the first day of the recruitment year.
- (ii) From amongst such Personal Assistants, Grade-1, in the pay scale of Rs 9300-34800 (Grade Pay, 4200) who have completed 5 years continuous service in their cadre on the first day of the recruitment year.

Provided that:--

The employees having service more than the prescribed service period on these feeder posts shall be placed at the top in the eligibility list.

Reservation 6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment;

Part- IV- Procedure for Recruitment

Termination

vacancies

7. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year in accordance with the rules, for the time being in force and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand under rule 6.

Procedure for

Recruitment

- 8.(1) Recruitment by promotion to the cadres of the Service shall be made by selection on the basis of seniority, subject to rejection of unfit from amongst the employees, who are eligible for promotion under rule 5 of part-III through the selection committee.
- (2) The selection Committee shall comprise the following:-
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| (i) Chairman, Commercial Tax Tribunal | Chairman/Appointing Authority |
| (ii) Member, Commercial Tax Tribunal | Member |
- (3) The Appointing Authority shall determine the number of each category of vacancies for which selection is to be made.
- (4) The eligibility list of all the candidates included in the field of eligibility along with their character rolls and all such other records, if any, as may be considered necessary and relevant for the purpose, shall be placed before the selection committee.
- (5) The selection Committee, for the purpose of determining the suitability of the candidates eligible for promotion to the post for which selection is to be made, shall consider the cases of all the candidates with reference to their character rolls and other records pertaining to them, placed before it.
- (6) The names of the candidates selected by the selection committee shall be arranged in order of seniority in the cadre from which they are promoted. The names of the candidates in the selection list so prepared shall be twice the number of vacancies for which selection is to be made.
- (7) Thereafter the Appointing Authority shall, in accordance with the rules, issue promotion orders of the candidates recommended for promotion by the Selection Committee.

Part- V- Seniority, Probation and Confirmation

Seniority

- 9.(1) Except as hereinafter provided, the seniority of a person shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants (Seniority) Rules, 2002. If two or more persons are appointed together, their seniority shall be determined by such order in which their names are arranged in the appointment order;
- If the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date will be

deemed to be the date of order of substantive appointment and in other cases it will mean the date of issue of the order;

Provided further that if more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, the inter se seniority of the candidates shall be the same as mentioned in the combined appointment order issued under rule 15 of the Uttarakhand Government servants (Seniority) Rules, 2002.

- (2) The inter se seniority of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted;

Provided That-

(i) Where appointments from any source fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or year, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, however, in the combined list to be prepared under this rule their names shall be placed at the top followed by the names, of the other appointees in cyclic order.

(ii) Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure, be filled from the other source and appointments in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies in accordance with the quota.

Section 10. (1) Every person on appointment to a post in the service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken in to account for the purpose of computing the period of probation.

(3) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases, specifying the date upto which the extension is granted;

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(4) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his/ her opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he/she may be reverted to

his/her substantive post if any, and if he/she does not hold a lien on any post, his/her services may be dispensed with.

(5) A probationer, who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule(4), shall not be entitled to any compensation.

Confirmation 11.(1) A probationer shall be confirmed in his/her appointment at the end of the period of probation or extended period of probation if-

(a) his/her work and conduct is reported to be satisfactory,

(b) his/her integrity is certified, and

(c) the Appointing Authority is satisfied that he/she is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttarakhand Government Servant (Confirmation) Rules, 2002 confirmation is not necessary, the order, passed under sub-rule(3) of rule 5 of these rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation period, shall be deemed to be the order of confirmation.

Part- VI- Pay etc.

Scales of Pay 12.(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules shall be as follows:-

S.N.	Designation	Name of Pay Scales /Pay Band	Pay Band/ Pay Scales	Pay Band
1	2	3	4	5
1.	Assistant Registrar, Commercial Tax Tribunal, Uttarakhand	Pay Band-2	Rs.9300-34800	4600

Pay during

Probation 13.(1) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental rules;

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not account for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

Part-VII- Other Provisions

Convassing 14. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service, will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his/her candidature, will disqualify him/her for appointment.

ation of
er matters

15. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, the persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.


**Relaxation in the
conditions of
Service**

16. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

17. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other Special categories of candidates in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,


(Rakesh sharma)

Additional chief Secretary.